

342

उत्तराखण्ड शासन
राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2
संख्या 1024 / xxxii-2-2015-02(01)/2010 Part-III
देहरादून: दिनांक 22 जुलाई, 2015

कार्यालय-आदेश

शासन के उच्चाधिकारियों के साथ सम्बद्ध एवं राज्य सम्पत्ति पूल के स्टाफ कारों में दिनांक 01-05-2015 से 31-05-2015 (मई, 2015) तक की अवधि में मै0 मेघदूत सर्विस स्टेशन, 48, गांधी रोड, देहरादून से आपूर्ति पी0ओ0एल0 से संबंधित मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड के माध्यम से प्राप्त संलग्न कुल 32 बीजकों की कुल धनराशि ₹ 12,07,855.00 (₹ बारह लाख सात हजार आठ सौ पचन मात्र) का भुगतान शासनादेश संख्या-439/xxxii(1)/01(एक)-01/बजट-मुख्य/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2015 आबंटन पत्र संख्या - 439/xxxii(1)(one)-01/Budget/2015-16, अलोटमेंट आई डी-H1504070092 आबंटन पत्र दिनांक 10 अप्रैल, 2015 द्वारा वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के निवर्तन पर विभिन्न मदों में आवंटित बजट की सुसंगत मद से आहरित कर सम्बन्धित फर्म को किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को सम्बन्धित फर्म के पंजाब एण्ड सिंध बैंक की गांधी रोड स्थित शाखा में खाता संख्या-00051600000009, आई0एफ0एस0सी0 कोड संख्या-PSIB00000005 में नियमानुसार आयकर की कटौती सुनिश्चित करते हुए, जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। संबंधित फर्म का पैन नं0- AAIFM3637P, टिन नं0- 05005678793 एवं मो0नं0- 8171175310 है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-091-कार्यालय व्यय 03-राज्य सम्पत्ति विभाग 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक- यथोपरि।

(विनय शंकर पाण्डेय)

अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

संख्या: 1024 / xxxii-2-2015-02(01)/2010 Part-III, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय केन्द्रीय/निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून।
- 3- वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन/अनु सचिव, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- 4- मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, देहरादून।
- 5- सम्बन्धित फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बीजकों में दोहरा भुगतान नहीं लगाया गया है, यदि कालान्तर में दोहरे भुगतान की स्थिति संज्ञान में आती है, तो इसके लिये फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी तथा यह भी कि उक्त भुगतान के प्राप्त होने के पश्चात इसकी सूचना मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग को, उनके संगत अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 6- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन/एन0आई0सी0, देहरादून/बजट सहायक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

21/7

(एम0एम0सेमवाल)

संयुक्त सचिव।